

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

प्रेस  
विज्ञापित

बजट 2021-22

24 फरवरी, 2021

## बजट वर्ष 2021-22 के प्रमुख बिन्दु

### राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में ₹ 1 लाख 84 हजार 330 करोड़ 13 लाख की राजस्व प्राप्तियां
  - वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में ₹ 2 लाख 8 हजार 80 करोड़ 17 लाख का राजस्व व्यय
  - वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा ₹ 23 हजार 750 करोड़ 4 लाख
  - वर्ष 2021-22 का राजकोषीय घाटा ₹ 47 हजार 652 करोड़ 77 लाख जो GSDP का 3.98 प्रतिशत है
- प्रदेश में पहली बार **पेपरलैस बजट**

### कोरोना प्रबंधन :

- विशेष कोविड पैकेज की घोषणा
- 33 लाख असहाय परिवारों को दो हजार रुपये की सहायता
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 हजार नये लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी
- स्टार्टअप को Seed Money, 5 लाख रुपये प्रति स्टार्टअप
- Back to School कार्यक्रम, निःशुल्क यूनिफार्म व पाठ्यपुस्तकें, 470 करोड़ रुपये खर्च
- सहरिया, कथौड़ी जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों को **200 दिवस का रोजगार**

### चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं :

- 'Rajasthan Model of Public Health' (RMPH)
- 'Universal Health Coverage', प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा
- 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय
- संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से Public Health College
- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या में वृद्धि
- राज्य के चिकित्सालयों में भवनों का निर्माण, चिकित्सा सुविधा व बेड क्षमता में वृद्धि
- प्रदेश में 30 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) खोले जायेंगे।
- 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- चिकित्सा संस्थानों को **जिला अस्पताल** में क्रमोन्नत, 10 नवीन ट्रोमा सेन्टर खोले जायेंगे,
- 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण, लगभग 206 करोड़ रुपये व्यय

- कोटा में 150 बेड क्षमता के नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना,
- विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1 हजार बेड्स की वृद्धि
- 12 हजार चिकित्सा केन्द्रों को health and wellness centre के रूप में
- अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 'मॉडल CHC'
- जिला अस्पताल, पावटा—जोधपुर की बेड क्षमता वृद्धि तथा आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु 25 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय
- मेडिकल कॉलेज में नवीन ICU, NICU व जिला चिकित्सालयों में भी नवीन ICU
- जयपुर में Institute of Tropical Medicine and Virology व Institute of Cardiology की भी स्थापना
- SMS Medical College, Jaipur में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार
- जोधपुर में 'Umaid Post Graduate Institute of Maternity and Neonatology' की स्थापना व 'Regional Cancer Institute' की स्थापना,
- 22 Advance Life Support (ALS) क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस
- 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालय
- उदयपुर व जोधपुर में Yog and Naturopathy के कॉलेज
- जोधपुर में 'International Centre of Excellence in Panchkarm'
- समस्त जिला चिकित्सालयों में 8 विशिष्टताओं में Post MBBS Diploma Courses
- विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर, Hospital Management Cadre का गठन
- 'Directorate of Food Safety' बनाये जाने की घोषणा

#### सड़क सुरक्षा –

- 'जीवन रक्षक योजना' (JRY)
- Integrated Traffic Management System (ITMS)
- 40 CHC को चिन्हित कर Primary Trauma Centre
- समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
- नये जिला परिवहन कार्यालय तथा उप जिला परिवहन कार्यालय

#### शिक्षा :

- विद्यालयों में स्मार्ट टीवी एवं सेटटॉप बॉक्स, 82 करोड़ रुपये का व्यय
- 2 वर्षों में English Medium के लगभग 1 हजार 200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय
- विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, 450 करोड़ रुपये की लागत

- 'शांति एवं अहिंसा निदेशालय' की स्थापना
- जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज (Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences-MGIGSS)
- जोधपुर में Fintech Digital University
- जयपुर में Rajasthan Institute of Advanced Learning
- नवीन महाविद्यालयों एवं नवीन कन्या महाविद्यालयों, संस्कृत महाविद्यालय, आईटीआई की स्थापना
- मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़-चूरु, कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर-भीलवाड़ा, किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, कुंवारिया-राजसमंद व भीण्डर-उदयपुर में गजेन्द्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा
- जयपुर में 200 करोड़ रुपये से Rajiv Gandhi Centre of Advance Technology (R-CAT)
- Guest Faculty हेतु विद्या संबल योजना,
- लगभग 1 हजार 500 राजकीय विद्यालयों में Science & Space Club

#### युवा एवं रोजगार :

- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2019 में बेरोजगार युवाओं को इंटरशिप व भत्ते को एक हजार रुपये से बढ़ाना,
- राजीव गांधी युवा कोर (RYC) का गठन, 2 हजार 500 'राजीव गांधी युवा मित्र, 50 हजार राजीव गांधी युवा Volunteers
- समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test), one-time verification system
- परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा
- आगामी 2 वर्षों में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां
- मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना
- मोरोली-भरतपुर में खेल स्टेडियम एवं काछवा-सीकर में भी खेल सुविधायें
- अजमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं कोटा संभाग मुख्यालयों पर खेलों हेतु मल्टीपरपज इंडोर हॉल
- राजसमन्द, सिरोही जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम एवं प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय पर लोकप्रिय खेलों का Tournaments, 30 करोड़ रुपये का प्रावधान
- जोधपुर एवं जयपुर में नये Residential Sports School
- बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम, जोधपुर के सुदृढीकरण कार्य, 20 करोड़ रुपये की लागत
- डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैण्डबॉल एकेडमी

### कृषक एवं पशुपालक कल्याण :

- आगामी वर्ष से 'कृषि बजट' की शुरुआत
- ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में 16 हजार करोड़ रुपये के ऋण, 3 लाख नये किसान, मत्स्य पालक व पशुपालक सम्मिलित
- 'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना', 3 लाख कृषकों को निःशुल्क Bio Fertilizers एवं Bio Agents, तीन लाख कृषकों को 'micro nutrients kit', 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज
- प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क, 200 करोड़ रुपये का व्यय,
- मथानिया-जोधपुर में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क
- आगंगवा-जोधपुर में ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी 60 करोड़ रुपये का व्यय
- एक हजार किसान सेवा केन्द्र, कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार नये पद
- किसानों को बिजली हेतु सब्सिडी-16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान
- नयी कृषि विद्युत वितरण कम्पनी
- 50 हजार किसानों को सोलर पम्प तथा अन्य 50 हजार किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन
- कृषि उपज मंडी समितियों में एक हजार करोड़ रुपये की लागत के कार्य
- जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स पर 20 करोड़ रुपये की लागत
- डूंगरपुर, हिण्डौली व हनुमानगढ़ में 3 नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना
- चरणबद्ध रूप से एक हजार कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना, 20 करोड़ रुपये की लागत
- '102-मोबाइल वेटेनरी सेवा', 48 करोड़ रुपये का व्यय
- पशु चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार, 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों व 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत
- प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन
- राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह
- नंदी शालाओं के लिए 111 करोड़ रुपये

### उद्योग :

- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए नई नीति
- 64 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
- 'Greater Bhiwadi Industrial Township' की घोषणा, एक हजार करोड़ रुपये का निवेश
- नया 'Marwar Industrial Cluster' बनाने की भी घोषणा, 750 करोड़ रुपये
- जयपुर में Rajasthan Investors Summit का आयोजन

- जयपुर में Fintech Park (Financial Technology Park)
- जोधपुर में Biotech-Pharma Business Incubation & Research Centre
- Rural i-Start कार्यक्रम वृहद् स्तर पर लागू

#### सामाजिक सुरक्षा :

- 'राजस्थान पैटर्न'
- Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development कानून
- 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना'
- अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, पांच हजार छात्र लाभांशित
- 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल
- 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों के भवनों का निर्माण, 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय
- 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण
- 3 अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय
- जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास
- SC, ST, OBC व Minority विकास कोष, प्रत्येक हेतु 100 करोड़ रुपये
- देवनारायण योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का पैकेज, MBC हेतु 3 छात्रावासों का निर्माण
- Denotified Tribes (DNT) Policy लायी जायेगी
- विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि
- दिव्यांग छात्र-छात्राओं तथा युवाओं को दो हजार Scooty, 15 करोड़ रुपये व्यय
- संभाग मुख्यालयों पर समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना
- जिला मुख्यालयों पर गौरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन
- 25 हजार आंगनबाड़ियों को नन्द घर योजना में सम्मिलित करना
- सभी महिलाओं को भी, आवश्यकतानुसार सेनेटरी नेपकिन सुविधा, 200 करोड़ रुपये का प्रावधान
- जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना, 15 करोड़ रुपये का व्यय
- जनजाति क्षेत्रों में 250 माँ-बाड़ी केन्द्र
- 150 वनधन केन्द्रों का गठन किया
- वीरंगनाओं एवं अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को देय सम्मान भत्ता 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह
- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार प्रतिमाह
- देवस्थान विभाग के पुजारियों के मानदेय में वृद्धि

## आधारभूत संरचना :

### सड़क-शहरी विकास :

- नवीन राज्य सड़क नीति-2021
- कुल एक हजार करोड़ रुपये की राशि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन-पेचेबल या मिसिंग लिंक सड़क के कार्य
- सभी जिलों में 7 हजार 257 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का क्रमोन्नयन
- प्रत्येक जिले के तीन प्रमुख सड़क मार्गों के मेजर रिपेयर कार्य लगभग 1900 करोड़ रुपये की लागत से
- नगर निगमों की 30 किलोमीटर, नगर परिषदों की 20 किलोमीटर व नगर पालिकाओं की 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य
- आगामी दो वर्षों में 2 हजार 841 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों पर 1 हजार 425 करोड़ रुपये खर्च
- 3 हजार 880 करोड़ रुपये की लागत 27 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य
- 403 करोड़ रुपये की लागत से 8 ROB का निर्माण
- 8 रेल फाटकों पर ROB के निर्माण हेतु डीपीआर
- बूंदी जिले में High Level Bridge, 37 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत
- कोटा जिले में High Level Bridge के निर्माण हेतु डीपीआर
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से लगभग 3 हजार आवासों का निर्माण
- बेणेश्वर धाम में 132 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से पुल का निर्माण
- Constitutional Club, Jaipur बनाना प्रस्तावित
- जयपुर शहर में लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य
- भरतपुर शहर में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम, लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय
- कोटा शहर में सुचारु यातायात के लिए विभिन्न निर्माण कार्य, 140 करोड़ रुपये व्यय
- जोधपुर शहर में looping route ,हेरिटेज संरक्षण का कार्य, 100 करोड़ रुपये का व्यय
- बीकानेर में सड़कों के विभिन्न निर्माण कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय
- उदयपुर शहर में विभिन्न निर्माण आदि कार्य पर 150 करोड़ रुपये का व्यय
- जोधपुर में 60 करोड़ रुपये से आधुनिक ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर का निर्माण
- दौसा, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर एवं बूंदी में टाउनहॉल
- ग्रामीण बस सेवा पुनः प्रारंभ, लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को लाभ

### पेयजल—जल संसाधन :

- जल जीवन मिशन में लगभग 4 हजार 700 करोड़ रुपये की 12 नवीन वृहद् पेयजल परियोजनाओं का काम, 1 हजार 428 गांव एवं 1 हजार 891 ढाणियां लाभांवित
- जल जीवन मिशन 2 हजार 285 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जायेगा, जिससे 2 हजार 686 गांव एवं 2 हजार 453 ढाणियां लाभान्वित
- जल जीवन मिशन में लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन
- जल जीवन मिशन के तहत 22 परियोजनाओं की DPR
- विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत 476 करोड़ रुपये के कार्य
- चम्बल—भीलवाड़ा पेयजल परियोजना—1 हजार 32 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ
- नोखा—बीकानेर पेयजल परियोजना—750 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ
- कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु आगामी वर्ष में, 7 हजार 700 करोड़ के कार्य
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवेल
- जोधपुर शहर की 10 आवासीय योजनाओं में पेयजल की सुचारु व्यवस्था हेतु लगभग 76 करोड़ रुपये व्यय
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) कार्य, कुल 320 करोड़ रुपये का प्रावधान
- परवन वृहद् सिंचाई परियोजना पर 885 करोड़ रुपये का प्रावधान
- राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project-RWSLIP) पर 465 करोड़ रुपये खर्च, 21 जिले लाभांवित
- रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area- RWSRPD) के अन्तर्गत लगभग 378 करोड़ रुपये के जीर्णोद्धार कार्य
- रिपेयर—रिनोवेशन—रेस्टोरेशन (RRR) योजना में 124 करोड़ 71 लाख रुपये के 37 कार्य

### ऊर्जा :

- ऊर्जा नीति: 2021—2050
- राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का **ग्रीन कॉरिडोर**

### वन एवं पर्यावरण :

- सामुदायिक वन अधिकार पट्टे हेतु अभियान



- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर को Wetland Birds Habitat Conservation Centre के रूप में विकसित
- तालछापर अभ्यारण्य, चूरु में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र
- जोधपुर में 'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन'
- 24 जिलों के 50 शहरों में FSTP, 200 करोड़ रुपये का व्यय
- प्रदेश के बड़े अस्पतालों में 25 करोड़ रुपये की लागत से Sewerage Treatment Plants

#### पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

- पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- शेखावाटी पर्यटन सर्किट विकसित किया जायेगा
- गोडवाड पर्यटन सर्किट विकसित किया जायेगा
- RTDC द्वारा संचालित 7 Midway का 10 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार
- प्रमुख तीर्थस्थलों का धार्मिक पर्यटन सर्किट, 100 करोड़ रुपये की लागत
- पुष्कर-अजमेर में Tourist Complex
- जैसलमेर में ढोला मारु Tourist Complex की DPR, Rajasthan Folk Art Training Institute की स्थापना
- कलाकार कल्याण कोष में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान
- फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति
- राजस्थान दिवस पर 'राजस्थान उत्सव' का आयोजन
- 5 हजार प्रतिभाशाली युवाओं, कलाकारों एवं साहसिक खिलाड़ियों के लिए Nehru Youth Cultural Exposure Programme

#### कानून व्यवस्था :

- Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) प्रभावी रूप से लागू
- नये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय; पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तथा सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय
- पुलिस चौकियों को पुलिस थाने में क्रमोन्नयन, 25 नवीन पुलिस चौकियां
- जयपुर आयुक्तालय में तीन नवीन थाने बनाये जायेंगे
- Rajasthan Police Infrastructure Development Corporation
- जेलों में बुनियादी सुविधाओं संबंधी कार्य, लगभग 31 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत
- ACB में Digital Voice Logger की स्थापना
- प्रदेश में विभिन्न 40 नये न्यायालयों की स्थापना

## सुशासन :

- Social & Performance Audit Authority का गठन
- नये एडीएम, नवीन उपखण्ड , तहसील, उप तहसील कार्यालय
- सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय,
- 6 नई नगर पालिकाओं का गठन
- भूतपूर्व सैनिकों की सरकारी सेवा में lateral entry, लगभग 5 हजार भूतपूर्व सैनिकों को लाभ
- 1 मई, 2021 से 'प्रशासन गांवों के संग' तथा 2 अक्टूबर, 2021 से 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान
- 3 हजार करोड़ रुपये की राशि से कार्मिक कल्याण कोष
- 10 करोड़ रुपये की राशि Bar Council of Rajasthan को सहायता के रूप में
- Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करने की घोषणा
- कोरोना के कारण डेफर किये गये वेतन को जारी करने की घोषणा
- संविदाकर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने की घोषणा, विभागवार Cadre
- HCM RIPA, जयपुर में 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम

**प्रेस नोट**  
**बजट 2021-22**

**कर प्रस्ताव**

राज्य के उद्यमी, रियल एस्टेट व्यवसायी, पर्यटन इकाइयां, व्यापारी, किसान, आमजन आदि के साथ-साथ राज्य सरकार के राजस्व पर कोविड 19 से विपरीत प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार को वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक बजट अनुमानों से 32 प्रतिशत राजस्व कम मिला है। वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले कर राजस्व के हिस्से में राज्य को 14 हजार करोड़ 94 लाख रुपये कम प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद बजट 2021-22 में कोई नया कर नहीं लगाया गया है एवं सभी वर्गों को लगभग 910 करोड़ रुपये की राहत दी गयी है –

**1. आमजन**

- Used दुपहिया वाहन एवं कारों के स्वामित्व हस्तान्तरण पर Additional Motor Vehicle Tax में 50% छूट।
- e-Vehicles के क्रेता को SGST का पुनर्भरण एवं दुपहिया व तिपहिया e-vehicles की खरीद पर अनुदान।
- स्थानीय निकायों तथा राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी, DLC के बजाय Allotment राशि पर ली जायेगी।
- 14 जुलाई, 2014 के बाद निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों (मध्यवर्ती) पर स्टाम्प ड्यूटी DLC का 40 प्रतिशत लिया जायेगा।
- पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग पर स्टाम्प ड्यूटी मुक्ति का दायरा बढ़ाया।
- पुत्रियों के समान पुत्रवधुओं के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर 2.5% के स्थान पर 1% स्टाम्प ड्यूटी।
- पोता-पोती, दोहिता-दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति।
- मद्यसंयम हेतु स्व. श्री गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान।
- हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों का पुर्नवास, बच्चों की शिक्षा तथा नशामुक्ति हेतु 100 करोड़ रुपये से नवजीवन कोष।
- राजस्व अर्जन विभागों में स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का Refund, विद्युत शुल्क, खनिज जिप्सम के परमिट, परिवहन विभाग के Tax Clearance Certificate एवं परमिट आदि का सरलीकरण कर Online जारी किये जायेंगे।

- Security Bond पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये की जायेगी। ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टाम्प ड्यूटी के मामलों के लिये 1 अप्रैल, 2021 से एक नई Amnesty Scheme लायी जायेगी।

## 2. किसान

- मण्डी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं आढ़त को घटाकर किसानों को राहत।
- Colonisation Area के सभी श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की 30 जून, 2021 तक बकाया समस्त किश्तों पर ब्याज माफी तथा समस्त बकाया किश्तें जमा कराने पर मूल बकाया राशि में भी 10% छूट।

## 3. उद्यमी/निवेशक

- RIPS-2014 की कार्यावधि को 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक।
- Land Tax पर ब्याज एवं शास्ति में छूट की तिथि 30 जून, 2021 तक।
- "Gems & Jewellery Bourse" को RIPS-2019 के सेवा क्षेत्र में जोड़ा जायेगा।
- Healthcare Sector एवं API को RIPS-2019 के Thrust Sector में जोड़ा जायेगा।
- Solar and Wind Manufacturing Enterprises को रोजगार अनुदान 75% से बढ़ाकर 90%.
- RIPS-2019 में e-Vehicles उत्पादन हेतु निवेश की शर्त को 50 करोड़ रुपये से कम करके 25 करोड़ रुपये।
- e-Vehicles Charging Stations and Swapping Stations को RIPS-2019 के Service Sector में Thrust Sector के लाभ।

## 4. SC/ST उद्यमी

- RIPS-2019 के अन्तर्गत "डॉ बी.आर. अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज" का प्रावधान किया जायेगा। जिसमें निवेश सीमा 50 प्रतिशत कम की जायेगी, EFCI को 150% से बढ़ाकर 200% किया जायेगा एवं ब्याज अनुदान अथवा पूंजी अनुदान दिया जायेगा। SC/ST उद्यमी के लिये Incubation Centres चलाये जायेगे।

## 5. Most Backward, Backward and Tribal Areas उद्यमी

- इन क्षेत्रों में "डॉ बी.आर. अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज" की भांति निवेश सीमा 50 प्रतिशत कम की जायेगी, EFCI को 150% से बढ़ाकर 200% किया जायेगा एवं ब्याज अनुदान अथवा पूंजी अनुदान दिया जायेगा।

## 6. Real Estate

- वाणिज्यिक व आवासीय DLC दर 10 प्रतिशत कम की जायेगी।
- 50 लाख रुपये तक की कीमत के मल्टी-स्टोरी फ्लेट पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 6 से 4 प्रतिशत।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत EWS तथा LIG में स्टाम्प ड्यूटी घटाकर क्रमशः 1 से 0.50 प्रतिशत एवं 2 से 1 प्रतिशत।
- Anywhere-Online Registration, DLC दरों का Technology से निर्धारण एवं GIS के साथ नगरीय विकास कर (UD Tax) व्यवस्था विकसित की जायेगी।

## 7. व्यापारी

- Sales Tax, VAT, Entry Tax, Entertainment Tax and Luxury Tax की बकाया मांग, विवाद निस्तारण एवं न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु पर कर, ब्याज एवं शास्ति में छूट हेतु **Amnesty Scheme-2021** लायी जायेगी। जो 30 सितम्बर, 2021 तक प्रभावी रहेगी। राज्य में प्रथम बार मूल Tax में भी छूट एवं कोई monetary ceiling नहीं। इसमें 3 चरण होंगे जो पहले आवेदन करेगा उसे अधिक छूट।
- e-way bill जारी करने की सीमा 50 हजार रुपये से 1 लाख।
- त्रुटिपूर्ण Declaration Forms को संशोधित करने तथा Declaration Forms को पेश करने की अवधि बढ़ायी जायेगी।

## 8. ट्रांसपोर्ट व्यवसायी (Transporters)

- ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन पर Motor Vehicle Tax में 3 वर्ष तक छूट।
- Transport Amnesty Scheme-2021 के तहत Motor Vehicle Tax के मामलों में ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जायेगी। ओवरलोडिंग एवं वजन कराने से इंकार आदि करने पर Compounding Fee कम किया जाकर पुराने Traffic offences पर भी लागू की जायेगी।
- स्टेज कैरिज के अन्य श्रेणी मार्गों के लिये Tax के 8 स्लेब।

## 9. पर्यटन एवं टूर ऑपरेटर्स (Tourism & Tour Operators)

- Resorts and Amusement Park के लिए RIPS-2019 में न्यूनतम भूमि शर्त कम करके Building Bye Laws के अनुरूप किया जायेगा।
- IATO/RATO द्वारा अनुमोदित वातानुकूलित लज्जरी बसों को 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक Monthly Tax में पूर्ण छूट।

## 10. खनन पट्टाधारी

- अप्रधान खनिज की खोज में निजी भागीदारी हेतु Non-exclusive Prospecting Licences (NEPL) दिया जाकर NEPL धारक की पूर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर नीलामी करके खनन पट्टे दिये जायेंगे।
- निजी खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन।

## 11. अलाभकारी सामाजिक संस्थायें

- अलाभकारी सामाजिक संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी, भू-रूपान्तरण शुल्क, Motor Vehicle Tax इत्यादि में छूट देने के लिये "Social Security Investment Promotion Scheme: SSIPS-2021" लायी जायेगी। विशेष मामलों में Customized Package दिया जायेगा तथा इन संस्थाओं के पक्ष में व्यक्ति/ संस्थाओं द्वारा गिफ्ट डीड करने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जायेगी।